Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding exploring the feasibility of creating new states in the country-Laid.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): आजादी के समय देश में बड़े राज्य थे, जिनका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से किया था, परन्तु आजादी के बाद कई छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, जिन्होंने काफी प्रगति भी की और प्रगति के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत किया । इसका एक उदाहरण गुजरात राज्य है, जो कि तब के बम्बई प्रान्त से अलग होकर बना, जिसने न सिर्फ आर्थिक रूप से प्रगति की, बल्कि अपनी संस्कृति को न सिर्फ देश में, बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई । इसी तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि राज्यों का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हुआ और आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों के निर्माण के उपरांत इन राज्यों ने काफी प्रगति भी की है । परन्तु देश में नए राज्यों की मांग अभी भी जारी है और इस मांग के लिए समय-समय पर जन आन्दोलन भी होते रहे हैं । इन नए राज्यों की मांग में बुंदेलखण्ड राज्य की मांग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है । बुंदेलखण्ड राज्य की मांग स्वतंत्रता पूर्व की मांग है । इस हेतु फरवरी, 1943 में टीकमगढ़ में बुंदेलखण्ड प्रान्त निर्माण सम्मेलन आयोजन किया गया और उसके उपरांत लगातार पृथक बुंदेलखण्ड राज्य की मांग होती रही है ।

बुंदेलखण्ड राज्य निर्माण की मांग का प्रमुख आधार विकास है । ब्रिटिश काल में ऐतिहासिक कारणों से बुंदेलखण्ड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले आर्थिक रूप से काफी पिछड़ गया और आजादी प्राप्ति के उपरांत दो राज्यों में बुंदेलखण्ड का विभाजन हो गया । संभवतः दो राज्यों में विभक्त होने वाला

बुंदेलखण्ड देश का एकमात्र क्षेत्र है । इन सभी कारणों के समग्र प्रभाव के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी इस क्षेत्र का विकास उस गति से नहीं हो पाया, जिस गति से अन्य राज्यों का निर्माण हुआ । इसके अतिरिक्त जहां अन्य राज्यों का विभिन्न आधार पर निर्माण हुआ और उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति की, वहीं अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन भी किया, परन्तु बुंदेलखण्ड में बोली जाने वाली बुन्देली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में भी जगह नहीं मिल पाई है और बुंदेलखण्ड की लोक संस्कृति के समक्ष अपने अस्तित्व को बचाने का संकट पैदा हो गया है ।

अत: स्वतंत्रता प्राप्ति एवं उसके पश्चात् बनाए गए छोटे राज्यों के सर्वांगीण विकास के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बुंदेलखण्ड के आर्थिक विकास और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु एवं बुंदेलखण्ड राज्य के संबंध में जनभावनाओं को देखते हुए, इस मांग को पूरा करने के लिए बुंदेलखण्ड राज्य का निर्माण अति आवश्यक है । इस हेतु मेरी सरकार से यह मांग है कि नवीन छोटे राज्यों के निर्माण और संभावनाओं की तलाश हेतु लघु राज्य निर्माण बोर्ड का गठन किया जाए ।